भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1406

जिसका उत्तर 27 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

6 अग्रहायण, 1941 (शक)

बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग योजना

1406. श्री रघु राम कृष्ण राजू:
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) यूनिट्स योजना का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार ने देश भर में बीपीओ संचालन को बढ़ावा देने के लिए भारत बीपीओ संवर्धन योजना को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बीपीओ को सरकार द्वारा दिए गए/दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से **(ग)** : ग्रामीण क्षेत्रों (मेट्रो स्थानों को छोड़कर) छोटे शहरों और नगरों में रोजगार के अवसर पैदा करने और आईटी/आईटीईएस उद्योग का प्रसार करने के लिए सरकार ने दो बीपीओ प्रोत्साहन योजनाएं नामत: इंडिया बीपीओ स्कीम (आईबीपीएस, 28 दिसम्बर, 2015 को शुभारंभ) और नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम (एनईबीपीएस, 30 जनवरी, 2015 को शुभारंभ) का शुभारंभ किया था। इन योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं और अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को प्रोत्साहन, स्थानीय उद्यमियों इत्यादि को प्रोत्साहन जैसे विशेष प्रोत्साहनों के साथ पूंजीगत और प्रचालन संबंधी व्यय के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधियन के रूप में प्रति सीट 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर 53,300 सीटों वाले बीपीओ/आईटीईएस प्रचालनों की स्थापना को प्रोत्साहन देना है। वित्तीय सहायता के संवितरण प्रत्यक्ष तौर पर इसके उद्देश्य यानि यूनिटों द्वारा रोजगार सृजन से जुड़े हुए हैं। इन योजनाओं के प्रारंभ से ही 257 यूनिटों ने देशभर के 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित कुल 48,519 सीटों के लिए बीपीओ/आईटीईएस प्रचालन प्रांरभ किए हैं जिससे प्रत्यक्ष रूप से लगभग 34,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। आईबीपीएस और एनईबीपीएस की अवधि दिनांक 31.3.2019 तक थी। पुनरावलोकन के बाद एनईबीपीएस को 1 वर्ष यानि 31.3.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

******